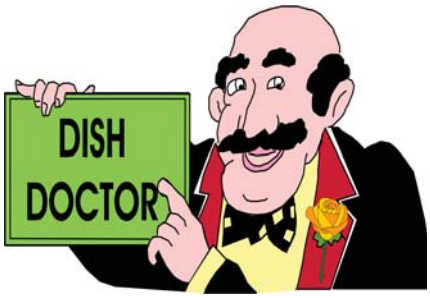

Ask us any questions or problems faced by you in the course of your business. Our DISH DOCTOR will try and answer them in the best way possible, in the simplest terms, avoiding the unnecessary use of technical terms where possible. The service is available free to our readers and subscribers.

Send Your Queries To: Dish Doctor, 312/313, A Wing,3rd Floor, Dynasty Business Park, Andheri Kurla Road, Andheri (E), Mumbai – 400059. or Email: manoj.madhavan@nm-india.com. Now you can WhatsApp Your Dish Doctor Queries To: +91-91082 32956

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (MIB)

Q: The I&B Ministry is the nodal body for broadcasting in India/ Please explain what are kind of role MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING plays?

Suryakant Pandit, Orissa

Ans.: Ministry of Information and Broadcasting (MIB) is the nodal ministry to issue broadcasting and cable services related license, permission and registration. The services include television (TV) broadcasters, FM broadcasters and the various Distribution Platform Operators (DPOs). These service providers are governed by different Guidelines/ Act issued by the Government. Broadly, MIB grants permissions for the various broadcasting services and the subsequent permissions to the existing service providers while serving the license, as per the following:

1. Permission for uplinking/ downlinking of TV Channels;
2. Permission for setting up of uplinking Hub/ Teleport/ SNG/ DSNG;
3. License to Direct-To-Home (DTH) operators;
4. Permission to Headend-In-The-Sky (HITS) operators;
5. Registration to Multi-System Operators (MSOs);

सत्यमेव जयते
Ministry of Information & Broadcasting
Government of India

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

प्रश्नः आईएंडबी मंत्रालय भारत में प्रसारण के लिए नोडल निकाय है। कृपया बतायें कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय किस प्रकार की भूमिका निभाता है?

सूर्यकांत पंडित, उड़ीसा

उत्तरः सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईवी) प्रसारण और केबल सेवाओं से संबंधित लाइसेंस, अनुमति और पंजीकरण जारी करने वाला नोडल मंत्रालय है।

सेवाओं में टेलीविजन (टीवी) प्रसारक, एफएम प्रसारक और विभिन्न वितरण प्लेटफॉर्म ऑपरेटर (डीपीओ) शामिल हैं। ये सेवा प्रदाता सरकार द्वारा जारी विभिन्न दिशा निर्देशों/अधिनियमों द्वारा शासित होते हैं। मोटे तौर पर एमआईवी विभिन्न प्रसारण सेवाओं के लिए अनुमतियां प्रदान करता है और बाद में लाइसेंस प्रदान करते समय मौजूदा सेवा प्रदाताओं को निम्न के अनुसार अनुमति देता हैः

1. टीवी चैनलों की अपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग के लिए अनुमति
2. अपलिंकिंग हब/टेलीपोर्ट/एसएनजी/डीएसएनजी की स्थापना के लिए अनुमति
3. डॉयरेक्ट–टू–होम (डीटीएच) ऑपरेटरों को लाइसेंस
4. हेडएंड–इन–द–स्काई (हिट्स) ऑपरेटरों को अन्नुमति
5. मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों (एमएसओ) के लिए पंजीकरण
6. स्थानीय केबल ऑपरेटरों (एलसीओ) के लिए पंजीकरण (प्रधान डाकघर द्वारा)

6. Registration to Local Cable Operators (LCOs) (by Head Post Office);
7. Permission for operating Internet Protocol Television (IPTV) services;
8. Permission for setting up FM Radio Station and Community Radio Stations (CRS);
9. Registration of Television Rating Points (TRP) Agencies;
10. Permission for temporary uplinking;
11. Permission for uplinking by the Indian News Agency;
12. Renewal of existing permissions;
13. Transfer of permission of television channels;
14. Permission for change in name, language, genre, logo, format of television channels;
15. Permission for change in the teleport, satellite of television channels;
16. Permission for Merger/ De-Merger/ Amalgamation;
17. Action for non-compliance/ breach of terms and conditions of the license;
18. Surrender of license/ permission/ registration;
19. Cancellation/ Revocation of license/ permission/ registration;
20. Release of Bank Guarantees (BGs).

In addition to MIB, these permissions involve clearances from other ministries and departments. This inter-alia includes Ministry of Home Affairs (MHA) for security clearance, Department of Space (DOS) for clearance of satellite use, Wireless Planning and Coordination (WPC) for frequency assignment and National Operations and Control (NOCC) for network clearances. Further, there is requirement of net-worth verification by empaneled auditors of MIB for permission for uplinking and downlinking of TV channels. Additionally, for downlinking permission, the application is forwarded to the Department of Revenue for verification to conclude agreements on advertising, subscription revenue and programme content between the applicant (downlinking) company and the channel owner, in case the two are different entities. ■

7. इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन (आईपीटीवी) सेवाओं के संचालन की अनुमति
8. एफएम रेडियो स्टेशन और सामुदायिक रेडियो स्टेशन (सीआरएस) स्थापित करने की अनुमति
9. टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट्स (टीआरपी) एजेंसियों का पंजीकरण
10. अस्थायी अपलिंकिंग की अनुमति
11. भारतीय समाचार एजेंसी द्वारा अपलिंकिंग की अनुमति
12. मौजूदा अनुमतियों का नवीनीकरण
13. टेलीविजन चैनलों की अनुमति का हस्तांतरण
14. टेलीविजन चैनलों के नाम, भाषा, शैली, लोगो, प्रारूप में परिवर्तन की अनुमति
15. टेलीपोर्ट, टेलीविजन चैनलों के सैटेलाइट में परिवर्तन की अनुमति
16. विलय/डी-विलय/समामेलन की अनुमति
17. अनुज्ञप्ति के नियम व शर्तों का पालन न करने/उल्लंघन करने पर कार्रवाई
18. लाइसेंस/पंजीकरण/अनुमति का अभ्यर्पण
19. लाइसेंस/अनुमति/पंजीकरण रद्द करना/निरस्त करना
20. बैंक गारंटी जारी करना

एमआईबी के अलावा, इन अनुमतियों में अन्य मंत्रालयों और विभागों से मंजूरी शामिल है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ सुरक्षा मंजूरी के लिए गृह मंत्रालय (एमएचए), सैटेलाइट मंजूरी के लिए अंतरिक्ष विभाग (डीओएस), फ्रीक्वेंसी असाइनमेंट के लिए वायरलेस योजना और समन्वय (डब्लूपीसी), और नेटवर्क मंजूरी के लिए राष्ट्रीय संचालन और नियंत्रण (एनओसीसी) शामिल है। इसके अलावा अपलिंकिंग की अनुमति के लिए एमआईबी के सूचीबद्ध लेखा परीक्षकों द्वारा नेटवर्थ सत्यापन की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त डाउनलिंकिंग अनुमति के लिए आवेदक (डाउनलिंकिंग) कंपनी और चैनल के मालिक के बीच विज्ञापन, सब्सक्रीप्शन आय और प्रोग्राम सामग्री पर अनुबंध समाप्त करने के लिए सत्यापन के लिए आवेदन राजस्व विभाग को भेजा जाता है। (यदि दोनों अलग संस्थायें हैं) ■